

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

“पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के डिफेंस एग्रीमेंट से मची हलचल, भारत ने फर्जी दावों पर दिया करारा जवाब”

Sanket Morankar

Published on 08 Aug 2026



पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक राजनीतिक और रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की ओर से इस समझौते को तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में भारत को लेकर कई दावे किए गए, जिन पर भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बड़ा रक्षा समझौता

दिए गए स्रोत के अनुसार, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।

समझौते को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, तीनों देशों में से किसी एक देश पर होने वाले हमले को तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसी वजह से इस समझौते की तुलना कुछ रिपोर्ट्स में 'इस्लामिक NATO' से की जा रही है।

हालांकि, इस समझौते को आधिकारिक रूप से 'इस्लामिक NATO' नाम दिया गया है या नहीं, यह स्रोत में स्पष्ट नहीं किया गया है।

भारत को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दावा

रक्षा समझौते के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए समझौते के जवाब में भारत ने इजरायल के साथ भी एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी शुरू कर दी है।

कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि भारत ने इजरायल के सामने रक्षा समझौते का प्रस्ताव रखा है। इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय की फैक्ट-चेक इकाई ने इस दावे को खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने बताया फर्जी

भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट-चेक विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की की मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए उसे फर्जी बताया।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत और इजरायल के बीच कथित नए रक्षा समझौते को लेकर वायरल किया जा रहा कंटेंट सही नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे ऐसे फर्जी और भ्रामक पोस्ट से सावधान रहने की अपील भी की।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस तरह के कंटेंट में गलत जानकारी का इस्तेमाल किया गया था और कथित तौर पर AI की मदद से तैयार किया गया कंटेंट भी प्रसारित किया जा रहा था।

तीन देशों के समझौते पर भारत की नजर

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन तीनों देशों के बीच हुए समझौते पर बारीकी से नजर रख रहा है।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग और बदलते रणनीतिक समीकरणों को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है।

क्या है समझौते का उद्देश्य ?

स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने इस समझौते को तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने वाला कदम बताया है।

इसका एक प्रमुख पहलू यह है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यही प्रावधान इस समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।

हालांकि, इस समझौते के भविष्य के प्रभाव और इसके व्यावहारिक स्वरूप को लेकर आगे और आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच बातचीत

इसी घटनाक्रम के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत होने की जानकारी भी सामने आई है।

स्रोत के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि, इस बातचीत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के रक्षा समझौते की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में पेश करने की पुष्टि स्रोत में नहीं की गई है।

‘इस्लामिक NATO’ को लेकर चर्चा तेज

पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम देशों के बीच व्यापक रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग की वकालत करता रहा है। ऐसे में सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए इस समझौते के बाद ‘इस्लामिक NATO’ को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं।

हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके आधिकारिक प्रावधानों, सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं और भविष्य में होने वाले सैन्य एवं रणनीतिक सहयोग के आधार पर ही किया जा सकता है।

भारत ने फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील की

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारत-इजरायल

रक्षा समझौते से जुड़े दावे को फर्जी बताया है ।

विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी सनसनीखेज खबर को बिना सत्यापन के आगे साझा न करें ।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा समझौते के बाद क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हुई हैं, लेकिन भारत के खिलाफ किसी विशेष 'कट' या भारत-इजरायल के नए रक्षा समझौते से जुड़े वायरल दावों को लेकर आधिकारिक पुष्टि और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों में अंतर रखना जरूरी है ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.